सेवानिवृत योजना (वी आर एस) शुरू की हैं। यह योजना 31 अगस्त, 1998 तक चलेगी। यह योजना आस्थगित भुगतान पर आधारित हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए इच्छुक कर्मचारी अपनी आयु के अनुसार मूल वेतन कर 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत, 100 प्रतिशत और मंहगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे। यह भुगतान अधिकतम 12 वर्ष की अवधि अथवा अधिवार्षिता आयु जो भी कम हो, तक जारी रहेगा इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत के समय भविष्य निधि, उपदान और छुटिटियों के नकदीकरण जैसे अंतिम लाभ भी दिए जाएंगे।

Patenting of a New Stainless Steel Process

2858. SHRI YADLAPATI VENKAT RAO SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether a new economical stainless steel process has been devised by India;

(b) if so, the details thereof, and

(c) the steps taken for its early patenting?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Shri Ranjan Sen working with Tata Korf Engineering Services Limited, Jamshedpur has claimed to have developed a new economical process of manufacturing stainless steel.

(b) As per Financial Express dated 9.6.1998, Shri Sen has claimed that the new stainless steel making process is based on blast furnace technology, which involves chemical reduction of a mixture of prepared and partially processed iron ore and chromite ore, by coke.

(c) The patent may be granted after all the conditions required, as per procedure, are fulfilled.

Use of Surplus Land of VSP

2859. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: DR. Y LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have agreed to return unutilised land of Visakhapatnam Steel Plant to the State Government for development of Gangavaram Miner Port;

(b) if so, the reasons for not issuing the sanctions in this connection; and

(c) if not, the plans to utilise the unused land given by the State Government for construction of the steel plant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (c) Based on the request from Andhra Pradesh State Government and after consultations with the State Govt, and Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), a decision has been taken to hand over 1100 acres of land for the purpose of development of a miner port at Gangavaram. This is subject to certain conditions which include inter-alia alternative land to that extent making available to RINL on 'land to land basis' by Govt, of Andhra Pradesh.

खनिजों के निर्यात लक्ष्य

2860. **श्री गोविन्द राम मिरी** : क्या इस्पात और खान मंत्रर यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-98 के दौरान खनिजों के निर्यात लक्ष्यों को संशोधित करके उनमें वृद्धि की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्या खनिजों के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति को भी संशोधित किया जा रहा हैं;

(घ) यदि हां, तो नई कार्यनीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा खनिजों के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। अतः उनके संशोधन का प्रश्न नहीं उठता। खनिजों का निर्यात वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर घोषित, आयात निर्यात नीति के अनुसार किया जाता हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 अनुसार निर्यात नीति में खनिज सूची स्थिति तथा देश की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। खनिजों का यथासंभव मूल्य वधित रूप से निर्यात करने के प्रयास किये जाएंगे।

Restructuring and Expansion of VSP

2861. SHRI N.R. DASARI Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have received representations from Members of Parliament and other quarters regarding restructuring of capital base and expansion of Visakhapatnam Steel Plant; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Yes, Sir.

(b) Basically these representations sought expeditious action in obtaining the approval of Government on capital restructuring of VSP. A decision, thereafter has been taken to grant the following financial reliefs to RINL:

(i) conversion of Rs. 791 crore interest free lean to 7% non-cumulative redeemable preference capital, redeemable after 2000-01; and

(ii) conversion of Rs. 542.47 crore of loan advanced to RINL from 1993-94 to 1995-96 into 7% non-cumulative preference capital redeemable after 10 years.

गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात की उत्पादन लागत

2862. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या पिछले 6 महीनों के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है;

(ख)ऐसी वृद्धि का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस वृद्धि से इस्पात के बाजार मूल्य में किस हद तक प्रभाव पड़ा हैं;

(घ)क्या ऐसे संयत्र प्रतिस्पर्धा करने, उत्पादन स्थिरता बनाये रखने में समर्थ हैं; और

(ड.)क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग की निगरानी कर रही हैं?

इस्पात और खान मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी,हां। आदान लागत में वृद्धि रूपए के मूल्य में गिरावट के प्रभाव से कच्चे माल आदि के आयात की उच्च लागत जैसे अनेक घटकों के कारण इस्पात की लागत में वृद्धि हुई हैं। इस अवधि के दोरान टिस्को में 1100 रूपए की वृद्धि होने की सूचना प्राप्त हुई हैं।

(ग)इस्पात उद्योग उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की पूर्णतः क्षतिपूर्ति की पाने में समर्थ नहीं हैं। बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किए जा रहे इस्पात के मूल्य स्थिर रहे हैं।

(घ) और (ड.) चूंकि इस्पात उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया हैं और नियंत्रण समाप्त कर दिया गया हैं अतः इसका भविष्य पूर्णतः बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करता हैं। उद्योग में अलग-अलग कंपनियों का भविष्य अनेक घटकों, जिनमें प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपनाई गई बाजार नीति शामिल है, पर निर्भर करता हैं। तथापि, 1998-99 के बजट में आयात शुल्क, आवास और अवसंरचना क्षेत्र के संबंध में घोषित किए गए उपायों के फलस्वरूप इस्पात की मांग की स्थिति में सुधार होने की आशा हैं।

Steel Plants in Public Sector

2863. DR. D. VENKATESHWAR RAO : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the policy to keep alive all steel plants in the public sector; and